कॉलेज शिक्षा विभाग की उपलब्धियाँ

राजस्थान सरकार ने आज प्रदेश के हर उपखंड में कॉलेज खोल दिये हैं। राजस्थान देश का एक अग्रणी राज्य है जहां 90 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। वर्ष 2018 तक प्रदेश में कुल 250 कॉलेज थे। पिछले साढ़े चार साल में राज्य सरकार ने 340 से अधिक नये कॉलेज खोले हैं, जिनके भवन निर्माण के लिए 2200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। पूरे प्रदेश में 240 से अधिक कॉलेज भवनों के निर्माण का काम प्रगति पर है। और 100 से अधिक कॉलेज भवनों का निर्माण भी जल्द शुरू हो जाएगा।

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिये 80 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया तथा स्नातक स्तर पर 133 नवीन विषय, स्नातकोत्तर स्तर पर 210 नवीन विषय व 91 नवीन संकाय प्रारंभ किये गये।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय को साल 2019 में राज्य सरकार ने फिर से शुरू किया, जिनके भवनों का निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही जोधपुर स्थित MBM इंजीनियरिंग कॉलेज को भी अपग्रेड कर विश्वविद्यालय बनाया है।

विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु राजस्थान हायर टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रुवमेंट स्कीम लागू करने हेतु 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 07 राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। नैक ग्रेड में सुधार एवं प्रोत्साहन के लिए महाविद्यालयों को 50 लाख तक की वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु योजना भी लागू की गयी है।

प्रदेश के स्टूडेंट्स का विदेश में पढ़ाई करने का सपना अब साकार हो रहा है। राज्य सरकार की राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विश्व के 150 नामी विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इस योजना में स्टूडेंट्स की संख्या 200 से बढ़ाकर अब 500 कर दी है तथा जिनकी पारिवारिक आय आठ लाख से कम है उन्हें प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से चयन किया जा रहा है।

होनहार छात्राएं कॉलेज आसानी से आ-जा सकें, इसके लिए काली बाई भील व देवनारायण स्कूटी योजना के तहत प्रदेश की छात्राओं को स्कूटियां वितरित की जा रही हैं। इन योजनाओं में स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर अब 30,000 कर दी गई है जिनका जल्दी ही वितरण किया जाएगा।

जो छात्राएं पढ़ना चाहती हैं लेकिन कॉलेज नहीं जा सकती हैं, उनके लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत UG/PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कॉर्सेज करवाएं जा

रहे हैं, और उनकी फीस सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इससे अब तक 8500 से अधिक छात्राओं को लाभ मिल चुका है।

प्रदेश के सरकारी कॉलेज से NET/SLET पास रिसर्च स्कॉलर्स को फैलोशिप के लिए एक नई योजना लागू की गई है, जिसके तहत 20,000 रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। साथ ही इन्हें इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 25,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी।

राजस्थान सरकार ने कॉलेज टीचर्स के शैक्षिक विकास के लिए 500 शिक्षकों को देश- विदेश के नामी इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च और ट्रेनिंग की सुविधा के लिए योजना जारी कर दी गई है। साथ ही कॉलेज शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर और एजुकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए जयपुर में फेकल्टी डवलपमेंट एकेडमी की स्थापना भी की जा रही है।

राजकीय महाविद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों में कौशल संवर्द्धन एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कैम्पस प्लेसमेंट और वोकेशनल कोर्स भी शीघ्र प्रारंभ किये जा रहे है |

प्रदेश में पहली बार राजकीय महाविद्यालयों के 1300 से अधिक Associate Professors को Professor के पद पर पदोन्नत किया गया है। इससे शोध को बढ़ावा मिलेगा और कॉलेजों की NAAC ग्रेडिंग में सुधार होगा।

सरकार ने सहायक आचार्य के पद पर 757 नियुक्तियां दी हैं और 1913 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। प्रदेश में करीब 30 साल बाद राजस्थान सरकार द्वारा लाईब्रेरियन व पीटीआई के 494 पदों पर भी भर्ती की जा रही है। साथ ही Raj-CES में भी 2000 से अधिक भर्ती जल्दी ही शुरू की जाएगी।

राजस्थान सरकार के इन्हीं प्रयासों से आज प्रदेश के कॉलेजों में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो (Gross Enrollment Ratio) 2018-19 में 22.7 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 26.1 प्रतिशत हो गया है।